NCW takes cognizance of Kerala sexual abuse case

https://english.publictv.in/ncw-takes-cognizance-of-kerala-sexual-abuse-case/

January 12, 2025

NEW DELHI: The National Commission for Women (NCW) has expressed grave concern over reports of sexual abuse involving a teenage girl by 64 individuals over four years in Kerala's Pathanamthitta district and issued directions for a fair and timely investigation into the matter.

The NCW has also instructed authorities to ensure the prompt arrest of all accused and provide the victim with the required support. Taking to its social media handle on X, NCW posted, "On the directions of Chairperson Vijaya Rahatkar, the National Commission for Women has taken serious note of reports of a teenage girl alleging sexual abuse by 64 individuals over four years in Kerala's Pathanamthitta district."

"While few accused have been arrested, the Commission strongly condemns this heinous crime and has directed authorities to ensure the immediate arrest of all accused, a fair and time-bound investigation, and necessary support for the victim, including medical and psychological care," said the Commission.

The NCW also said that a detailed action taken report has been sought within 3 days. Meanwhile, 14 people have been arrested in 5 cases registered so far in connection with the alleged sexual abuse of a now 18-year-old girl in Kerala's Pathanamthitta district. The Ilavumthitta police, which had registered two cases, had arrested 5 youths yesterday. Then today, the Pathanamthitta police registered 3 cases and immediately took 9 of the total 14 accused into custody.

Subin (24), VK Vineeth (30), K Anandu (21), S Sandeep (30), and Sreeni alias S Sudhi (24) are the accused in a case registered at the Ilavumthitta station. Achu Anand (21) is the accused in another POCSO case registered here. The fifth accused in the first case, Sudhi, is currently in jail in another POCSO case registered by the Pathanamthitta police earlier.

The investigation into this case, which has been filed under sections of the Prevention of Atrocities against Scheduled Castes Act, is being conducted by Pathanamthitta Deputy Superintendent of Police PS Nandakumar. The case was registered on the report of the Pathanamthitta Child Welfare Committee (CWC). Earlier in the day, the

National Human Rights Commission (NHRC) also took cognizance of the sexual abuse case in Kerala and said that it has written to the state government for action in this matter.

“Everyone should stand with the minor girl who has courageously raised her voice against the incidents of rape that happened to her for 5 years. It is very important that we all become her strength. We should appreciate her for showing courage. 64 people raped her continuously for 5 years. It means that the system has collapsed. We are writing to the state government for action in this matter as per the complaint,” NHRC member Priyank Kanoongo said. (ANI)

TIMES OF INDIA, Online, 13.1.2025
Page No. 0, Size:(0)cms X (0)cms.

NHRC moved on employment rights for educated youths

https://timesofindia.indiatimes.com/city/bhubaneswar/nhrc-moved-on-employment-rights-for-educated-youths/articleshow/117177866.cms

Jan 12, 2025, 09.29 PM IST

Bhubaneswar: NHRC has directed three central ministries to consider the right to employment of educated youths and technically qualified persons and ensure necessary action.

It passed the order after hearing a petition filed by human rights activist and lawyer Radhakanta Tripathy. The complainant, while referring to the 'India Employment Report-2024', drew the commission's attention to the issue of large-scale unemployment among the youth, especially from vulnerable strata, who are suffering immensely.

He submitted that talented, technically qualified persons are experiencing mental health issues due to a lack of employment or a proper place to utilise their talent and expertise. "Right to education and right to life are meaningless without the right to livelihood," the petitioner added.

The commission asked the secretaries of the ministry of education, the ministry of labour and employment, and the ministry of personnel and training to consider the concerns raised by the activist. TNN

चंद्रबाबू नेतृत्व के अयोग्य

https://www.arthparkash.com/chandrababu-unfit-for-leadership#google_vignette

- By **Sorit Chaudhary** -- Saturday, 11 Jan, 2025

ताडेपल्ली : Chandrababu unfit for leadership: (आंध्र प्रदेश) वाईएसआरसीपी नेता और राधारंगम मित्र मंडली के प्रदेश अध्यक्ष वंगावीति नरेंद्र ने मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की एक नेता के रूप में अप्रभावीता के लिए कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि नायडू केवल प्रचार में रुचि रखते हैं और लोगों की सेवा करने के लिए उनके पास वास्तविक इरादे नहीं हैं, उन्होंने नायडू पर सत्ता हासिल करने के लिए चुनावों के दौरान खोखले वादे करने और उन्हें पूरा करने में विफल रहने का आरोप लगाया। नरेंद्र ने टीटीडी के अध्यक्ष के रूप में बी.आर. नायडू जैसे अनुभवहीन नेताओं की नियुक्ति की आलोचना की, जिसके परिणामस्वरूप कुप्रबंधन हुआ। उन्होंने वैकुंठ एकादशी के दर्शन के लिए तिरुमाला जाने वाले भक्तों के लिए बुनियादी सुविधाओं की कमी को उजागर किया और तिरुपति में भगदड़ की घटना पर दुख व्यक्त किया, जिसमें छह लोगों की जान चली गई।
उन्होंने इस त्रासदी के लिए चंद्रबाबू नायडू को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया और उनकी गिरफ्तारी की मांग की।
नायडू के कार्यकाल के दौरान गोदावरी पुष्करालु भगदड़ के साथ समानताएं बताते हुए, जिसमें 29 लोगों की मौत हो गई थी, नरेंद्र ने लापरवाही के दोहराए जाने का आरोप लगाया। उन्होंने नायडू पर अप्रासंगिक व्यक्तियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियाँ सौंपने और अपने समुदाय से बाहर के लोगों के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया। इसके अलावा, नरेंद्र ने खुलासा किया कि तिरुपति की घटना के संबंध में **राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग**, केंद्रीय गृह मंत्री और राष्ट्रपति के पास शिकायत दर्ज कराई गई है। उन्होंने उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण से पीड़ितों के परिवारों से मिलने और प्रशासन की विफलताओं के लिए माफ़ी मांगने का आग्रह किया, उन्होंने जोर देकर कहा कि चंद्रबाबू मुख्यमंत्री का पद संभालने के लिए अयोग्य हैं।

रिटायर्ड अफ़सरों के बोझ तले दबा आरटीआई का ढाँचा

https://up18news.com/rti-structure-burdened-by-retired-officers/

January 12, 2025up18news

सेवानिवृत्त अधिकारी उन विभागों के खिलाफ निर्णय लेने में संकोच कर सकता है, जिनके लिए उन्होंने कभी काम किया था, जिससे समझौतापूर्ण फैसले होते हैं। पारदर्शिता में विशेषज्ञता की कमी एक बड़ा मुद्दा है। सेवानिवृत्त सिविल सेवकों में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक विशेष ज्ञान की कमी हो सकती है, जो आरटीआई अधिनियम का मुख्य हिस्सा है। सेवानिवृत्त नौकरशाह वर्तमान सामाजिक मुद्दों से कटे हुए हो सकते हैं, जिससे सार्वजनिक शिकायतों को प्रभावी ढंग से सम्बोधित करने की उनकी क्षमता कम हो सकती है। प्रशासनिक पृष्ठभूमि से आने वाले सूचना आयुक्त समकालीन दृष्टिकोण से सूचना तक पहुँचने के बारे में जनता की चिंताओं को पूरी तरह से नहीं समझ सकते हैं। लंबे समय तक सरकारी सम्बद्धता वाले नौकरशाहों की नियुक्ति से जवाबदेही कम हो सकती है, क्योंकि उनके निर्णय सरकारी हितों के साथ संरेखित हो सकते हैं। विशिष्ट राजनीतिक दलों से सम्बंध रखने वाले नौकरशाह सरकारी निर्णयों को चुनौती देने में अनिच्छा दिखा सकते हैं, जिससे आरटीआई ढांचे की स्वतंत्रता कम हो सकती है।

भारत में सूचना आयुक्तों के रूप में सेवानिवृत्त सिविल सेवकों के प्रभुत्व ने सूचना के अधिकार (आरटीआई) ढांचे की स्वतंत्रता और विविधता के बारे में चिंताएँ बढ़ा दी हैं। जबकि उनका अनुभव मूल्यवान हो सकता है, इस ने संभावित पूर्वाग्रहों और सीमित प्रतिनिधित्व पर बहस छेड़ दी है। इस तरह के प्रभुत्व के निहितार्थ और उम्मीदवारों के लिए पात्रता मानदंड को व्यापक बनाने के लिए सुधारों की आवश्यकता का पता लगाता है। आरटीआई ढांचे में स्वतंत्रता और विविधता के बारे में कई चिंताएँ हैं। सेवानिवृत्त सिविल सेवकों का प्रभुत्व एक संकीर्ण, एकरूप दृष्टिकोण बनाता है, जो निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में विविधता को कम करता है। सेवानिवृत्त नौकरशाहों को अक्सर प्रतिष्ठान का हिस्सा माना जाता है, जिससे सरकार की कार्रवाइयों को निष्पक्ष रूप से चुनौती देने की उनकी क्षमता सीमित हो जाती है। पूर्व सरकारी कर्मचारी अपने पूर्व सहयोगियों के प्रति पूर्वाग्रह प्रदर्शित कर सकते हैं, जिससे अपीलों को संभालने में निष्पक्षता कम हो सकती है।

एक सेवानिवृत्त अधिकारी उन विभागों के खिलाफ निर्णय लेने में संकोच कर सकता है, जिनके लिए उन्होंने कभी काम किया था, जिससे समझौतापूर्ण फैसले होते हैं। पारदर्शिता में विशेषज्ञता की कमी एक बड़ा मुद्दा है। सेवानिवृत्त सिविल सेवकों में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक विशेष ज्ञान की कमी हो सकती है, जो आरटीआई अधिनियम का मुख्य हिस्सा है। सेवानिवृत्त नौकरशाह वर्तमान सामाजिक मुद्दों से कटे हुए हो सकते हैं, जिससे सार्वजनिक शिकायतों को प्रभावी ढंग से सम्बोधित करने की उनकी क्षमता कम हो सकती है। प्रशासनिक पृष्ठभूमि से आने वाले सूचना आयुक्त समकालीन दृष्टिकोण से सूचना तक पहुँचने के बारे में जनता की चिंताओं को पूरी तरह से नहीं समझ सकते हैं। लंबे समय तक सरकारी सम्बद्धता वाले नौकरशाहों की नियुक्ति से जवाबदेही कम हो सकती है, क्योंकि उनके निर्णय सरकारी हितों के साथ संरेखित हो सकते हैं। विशिष्ट राजनीतिक दलों से सम्बंध रखने वाले नौकरशाह सरकारी निर्णयों को चुनौती देने में अनिच्छा दिखा सकते हैं, जिससे आरटीआई ढांचे की स्वतंत्रता कम हो सकती है।

सेवानिवृत्त सिविल सेवकों के प्रभुत्व का प्रभाव पड़ता है। जब चयन पूल में विविधता का अभाव होता है, तो जनता आरटीआई ढांचे की तटस्थता में विश्वास खो सकती है। सीमित नए दृष्टिकोण वाले नौकरशाहों का प्रभुत्व अक्षमता में योगदान देता है, जिससे आरटीआई अपीलों के प्रसंस्करण में देरी बढ़ जाती है। सीआईसी के 23, 000 अपीलों का बैकलॉग बताता है कि नए दृष्टिकोण के बिना नौकरशाही नियुक्तियाँ नागरिक शिकायतों के समय पर समाधान में बाधा बन सकती हैं। नियुक्तियों में विविधता की कमी के परिणामस्वरूप समान पृष्ठभूमि वाले कुछ व्यक्तियों के हाथों में शक्ति केंद्रित हो जाती है। यह प्रथा नवीन विचारों या दृष्टिकोण में परिवर्तन को रोकती है जो आरटीआई अधिनियम की प्रभावकारिता में सुधार कर सकते हैं। विविध इनपुट के बिना, आरटीआई ढांचा आधुनिक आवश्यकताओं के अनुकूल होने में विफल हो सकता है, जिससे सुधार रुक सकते हैं जो इसे और अधिक प्रभावी बना सकते हैं। अगर लोगों को लगता है कि निर्णय पक्षपातपूर्ण हैं या पूर्व सरकारी अधिकारियों द्वारा प्रभावित हैं, तो वे आरटीआई प्रक्रिया से जुड़ने के लिए कम इच्छुक महसूस कर सकते हैं।

योग्य उम्मीदवारों के पूल को व्यापक बनाने के लिए सुधारों की तत्काल आवश्यकता है। विभिन्न विशेषज्ञता वाले पेशेवरों को शामिल करने से निर्णय लेने में व्यापक दृष्टिकोण आएगा। यह आरटीआई ढांचे में विविध दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है। यूके जैसे देशों में, सूचना आयुक्त कानून, पत्रकारिता और शिक्षा जैसे पृष्ठभूमि से आते हैं, जो स्वतंत्रता और निष्पक्षता को बढ़ावा देते हैं। एक सार्वजनिक, पारदर्शी चयन प्रक्रिया निष्पक्षता को बढ़ावा देगी और सभी को सूचना आयुक्त की भूमिकाओं के लिए आवेदन करने का समान अवसर देगी। अमेरिका कई सरकारी निगरानी भूमिकाओं के लिए एक सार्वजनिक नामांकन प्रक्रिया का उपयोग करता है, जो उम्मीदवारों के चयन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करता है। कार्यकाल सीमित करने और आयु प्रतिबंध लागू करने से नए दृष्टिकोण को बढ़ावा मिल सकता है और सूचना आयोगों के भीतर गतिशील नेतृत्व की अनुमति मिल सकती है। ऑस्ट्रेलिया जैसे कई राष्ट्र वरिष्ठ अधिकारियों के कार्यकाल को सीमित करते हैं ताकि दीर्घकालिक रूप से जड़ता से बचा जा सके और नए विचारों को प्रोत्साहित किया जा सके।

नागरिक समाज के प्रतिनिधियों के साथ एक अधिक समावेशी दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करने में मदद कर सकता है कि आरटीआई प्रणाली जनता की ज़रूरतों के प्रति उत्तरदायी है। **राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग** में गैर-सरकारी संगठनों के सदस्य शामिल हैं, जो विविध दृष्टिकोणों के माध्यम से मानवाधिकारों के प्रति अपने दृष्टिकोण को मज़बूत करते हैं। आवेदनों के लिए आउटरीच और जागरूकता का विस्तार करना: रिक्तियों को सक्रिय रूप से प्रचारित करना और आउटरीच कार्यक्रमों को बढ़ाना विभिन्न पेशेवर पृष्ठभूमि से उम्मीदवारों को आकर्षित करने में मदद करेगा, जिससे अधिक विविध पूल बनेंगे। न्यूजीलैंड जैसे देश सार्वजनिक क्षेत्र की रिक्तियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान चलाते हैं, जिससे विभिन्न क्षेत्रों से कुशल पेशेवर आकर्षित होते हैं। आरटीआई ढांचे की स्वतंत्रता और विविधता सुनिश्चित करने के लिए, सुधार आवश्यक हैं। विविध क्षेत्रों के पेशेवरों को शामिल करके पात्र उम्मीदवारों के पूल का विस्तार करने से नए दृष्टिकोण आ सकते हैं, पूर्वाग्रह कम हो सकते हैं और जवाबदेही बढ़ सकती है। अधिक समावेशी दृष्टिकोण प्रणाली की पारदर्शिता को मज़बूत करेगा, जिससे दीर्घकालिक रूप से जनता का विश्वास बढ़ेगा।